'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2016-18
WPP Licence No.- U(C)-101/2016
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 30.09.2016
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज ;राम राजद्ध चेयरमैन – जस्टिस पब्लिकेशंस, टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फोन : 23354841–42

Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com

● वर्ष : 19 ● अंक 21 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 16 से 30 सितंबर, 2016

अगर सांवली रात खूबसूरत है तो सांवला चेहरा कैसे बुरा हो सकता हैं?

इति शरण

(मेरी दो बहनें हैं , एक गोरी है और एक सांवली। मैं दोनो से क्रमशः 10 और 12 साल बड़ा हूँ। टी. वी पर जब कभी फेयर एंड लवली का भोंडा , नस्लवादी विज्ञापन आता था तो छोटी उसे गौर से देखती, तब भी मैं चिढ़ता था , कभी –कभी डांट भी देता . लेकिन उसका समाज तो वही है –गोरेपन का आग्रही समाज। आज वह खुद को रेखा , शबाना आजमी और नंदिता दास के साथ खुद को जोड़ती है, गर्व से। कल इति शरण ने जब यह छोटी टिप्पणी स्त्रीकाल के लिए भेजी, तो मेसेज भी किया कि गुस्से से भरकर लिख रही हूँ, ठीक लगे तभी लीजिएगा। मैं सभी शेड्यूल्ड आलेख / रचनाओं को ड्राप कर आज इसे प्रकाशित कर रहा हूँ। काश कि समाज अपनी कुछ जड़ताओं से निकल पाता!

संजीव चंदन

काफी समय पहले नंदिता दास का यह पोस्टर फेसबुक में दिखा था। 'Stay Unfair, Stay Beautiful' बहुत खूबसूरत लगता है यह शब्द। गोरेपन की चाहत के भ्रम को तोड़ता और सांवलेपन से प्यार करना सिखाता है यह शब्द। अपने सांवलेपन को लेकर अफ़सोस करने वाली तमाम लड़कियों में आत्मविश्वास भरता हुआ दिखता है यह शब्द।

कभी मुझे भी मेरे इस सांवले रंग से चिढ़ होती थी, इसका कारण था सांवले रंग पर बचपन से लेकर आजतक लोगों से सुनी बातें। लोग सांवले रंग को लेकर हमारे ऊपर बेचारगी प्रकट करने में भी पीछे नहीं रहते। हमें गोरे होने के लिए ऐसी सलाह देते जैसे वे हमारे सबसे बड़े हितैषी हों।

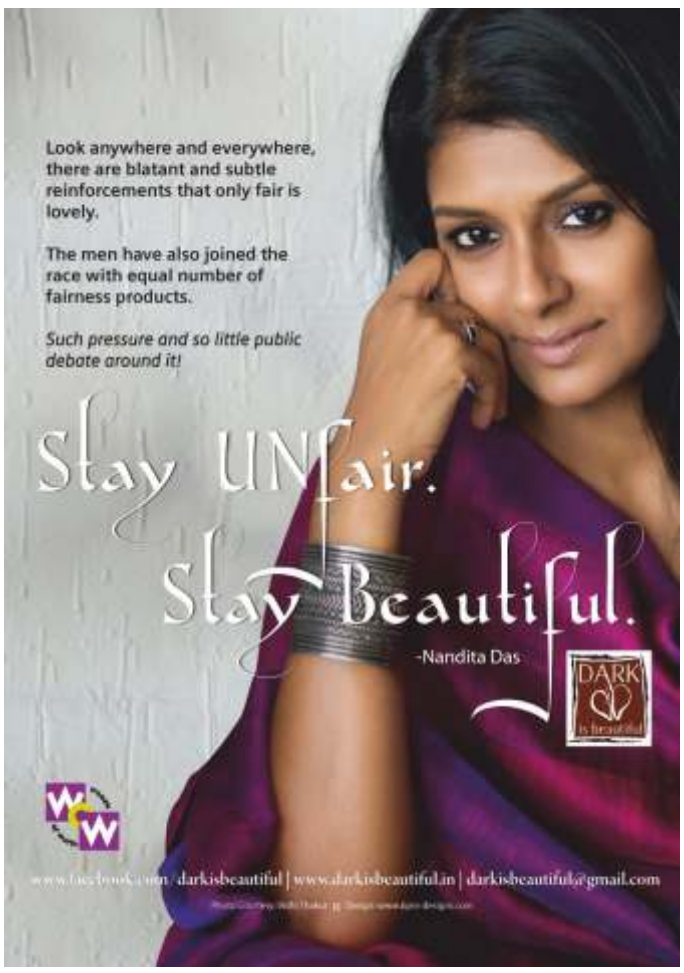

छोटी थी उस वक्त अक्ल भी नहीं थी। समाज में गोरे और सांवले रंग के बीच के दोहरे व्यवहार का मेरे दिमाग में भी असर पड़ता था। कई बार मैं माँ से बोलती भी थी, ''माँ तुम तो गोरी हो पर मुझे सांवला क्यों जन्म दिया।'' कई बार आईने में अपना चेहरा देखकर उदास भी हो जाती थी।

कुछ वैसे लोग जो मेरी माँ से मिले थे, मगर मेरे पिता जी से नहीं, मुझसे कहते थे, ''तुम काली कैसे हो गई जबकि आंटी तो गोरी हैं।'' मुझे बुरा लगता और मैं अपने बचाव में बस इतना ही कहती ''क्या है कि मैं अपने पापा पर गई हूँ।''

बाद में जब अक्ल आई तब अपनी ही सोच पर हंसी आने लगी। एक गोरे रंग को ही खूबसूरती का पैमाना बना बैठी थी मैं। जबसे उस गोरे रंग के भ्रम से निकली हूँ मुझे अपने सांवले रंग से प्यार हो गया है। अब अगर कोई फेयरनेस क्रीम लगाने की सलाह देता है, तो मुझे बहुत हंसी आती है।

अभी हाल में भी एक सज्जन मेरे सांवले रंग का मज़ाक बना रहे थे। उनका कहना था कि काले कपड़े की जगह मुझे ही खड़ा कर देना चाहिये फिर उस काले कपड़े की जरूरत ही नहीं होगी। छोटे में यह बात सुनी होती तो शायद उस वक्त खुद को बहुत अपमानित महसूस करती, क्या पता मेरी आँखों में आंसू भी आ जाते। पर अब नहीं, अब आंसू की जगह हंसी आती है। हंसी क्यों,

(शेष पृष्ठ 5 पर)

रैली की सफलता हेतु तैयारी सम्मेलन 9 अक्टूबर को मावलंकर हाल, दिल्ली में

अगर 28 नवंबर की रैली को अति सफल बनाना है तो उसके पहले प्रमुख साथियो की बैठक होना आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगामी 9 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक मावलंकर हॉल, कांस्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली में तैयारी बैठक रखी गयी है। इस सम्मेलन में सभी साथी न आएं तो भी चलेगा लेकिन जो जिला एवं प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उनको इस तैयारी बैठक में आना ही है। उन्हें भी आना है जो परिसंघ के आम कार्यकर्त्ता हैं। जो गत् 30 व 31 जुलाई को नहीं आ सके थे। बहुत सारे नए साथी जुड़े हैं, उन्हें इसमें भाग लेने का मौका मिलेगा। अतः उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित करें।

खाली हाथ आकर निराश न करें। जिनके पास सदस्यता की रसीदें हैं, जिस स्थिति में हों 9 अक्टूबर को जमा कर दें। आवश्यकता होगी तो फिर से जारी कर दिया जाएगा। बार–बार कहा जा चुका है कि फेसबुक, ट्वीटर, व्हाट्सअप, से जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा अपने समर्थकों का नाम, मोबाइल नं. व ईमेल भेजें। जो भेज चुके हैं, वे अन्यों से भेजने के लिए कहें और जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है और खुद की जिम्मेदारी महसूस करते हैं तो इस जिम्मेदारी को निभाएं।

याद रखें कि आपकी लड़ाई कोई और नहीं लड़ेगा, जिस दिन यह समझ पैदा हो गयी कि कर्मचारियों व अधिकारियों की उतनी ही जवाबदेही है, जितनी कि राजनैतिक प्रतिनिधियों की तो हमें अधिकार लेने से कोई नहीं रोक सकता। एक मानसिकता बन गयी है कि कर्मचारी–अधिकारी और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि सोचते हैं कि सांसदों, विधायकों, मंत्रियों व नेताओं से ही समाज के मान और अधिकार की लड़ाई लड़ी जानी है, तो उसे तोड़ना होगा। विधायकों, सांसदों व नेताओं की जो जिम्मेदारी है, वे जानते हैं और जो जानते और समझते नहीं हैं, उनको न तो समझाया जा सकता है और न ही डंडे के जोर पर काम लिया जा सकता है। बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर बौद्धिक नेतृत्व के निकम्मेपन पर भावुक हुए थे। बौद्धिक नेतृत्व मूलरूप से कर्मचारियों व अधिकारियों के पास है। हाल में जाट और पटेल आंदोलन आरक्षण के लिए हुए थे, जिसका नेतृत्व उनके समाज ने किया न कि उनके नेताओं ने। अगर वे जाति के नेताओं से उम्मीद लगाकर बैठे होते तो शायद यह आंदोलन न हो पाता।

– डॉ. उदित राज,राष्ट्रीय अध्यक्ष, अजा/जजा परिसंघ

www.facebook.com/parisangh.all.india
9717046047
@Parisangh1997
parisangh1997@gmail.com

सामान्यज्ञ से जी.एस.टी. को बचाया जाए

सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल और इसका सचिवालय बनाने के लिए सहमति दे दी है। इस दिशा में कार्य बड़ी तेजी से हो रहा है इसकी सराहना भी होनी चाहिए । काउंसिल एक्स ओफिसियो सेक्रेटरी से निर्मित होगा जो कि वित्त सचिव होंगे । उत्पाद एवं सीमा कर बोर्ड के चेयरमैन काउंसिल के स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे और जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा। काउंसिल में एक पद अतिरिक्त सचिव का होगा और 4 कमिश्नर इसके सचिवालय में जो भारत सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी के स्तर के होंगे। काउंसिल का जो सचिवालय होगा उसमे केंद्र एवं राज्य सरकारों के अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर होंगे । संविधान की धारा 179 (4), काउंसिल भारत एवं राज्य सरकारों को अपनी संस्तुति 'वस्तु एवं सेवा कर के सम्बन्ध में देने का कार्य करेगी जैसे कि कौन से विषय इससे बाहर होंगे, इसके नियम और कानून का निर्धारण इत्यादि। आपूर्ति की जगह से सम्बंधित नियम, वस्तु एवं सेवा कर दर, विशेष कर के दर का प्रावधान उन परिस्थितियों में जहाँ अतिरिक्त संसाधन जुटाना हो जैसे प्राकृतिक आपदा या किसी विशेष राज्य के लिए आदि ।

वस्तु एवं सेवा कर काउंसिल न केवल बेसुमार जिम्मेदारियों से घिरा हुआ है बल्कि इसका कार्य विशेषज्ञ का भी है । जो अच्छी जानकारी और ज्ञान रखते हैं, उन्हें आयकर अधिनियम, सीमा उत्पाद एवं सीमा शुल्क के अधिनियम समझ में नहीं आते, तो सामान्य व्यक्ति कैसे समझ पायेगा। अभी तक इन अधिनियमों को विशेषज्ञ लोग लागू किया करते थे जिनकी भर्ती इन्हीं के लिए की जाती थी । इतने लम्बे अनुभव के बाद भी कभी-कभी सलाह लेना या समझने के लिए मामले ये भी अग्रसारित करते हैं । जब अति विशेषज्ञ अधिकारी भी जानकारी और अनुभव में पूर्ण नहीं हैं तो सामान्य जानकारी रखने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कैसे इसे लागू कर सकते हैं। पूरी दुनिया विशेषज्ञों की दिशा में बढ़ रही है और हमारे प्रधानमंत्री तो विशेष रूप से जैसे डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया इत्यादि। काउंसिल के सेक्रेटरी का पद बहुत अहम है और इसलिये यह एक्स ओफिसियो न होकर स्थायी होना चाहिए। विशेषज्ञ का ही लगातार काउंसिल को सुझाव और मशविरा मिलना चाहिए ।

सौ से ज्यादा देशों ने जीएसटी को लागू कर दिया है और हर जगह विशेषज्ञ कर अधिकारी लगे हैं । कर जुटाना और उससे सम्बंधित प्रशासन बेहतर रूप से विशेषज्ञ ही कर सकते हैं । जीएसटी रेट तय करना, कर सीमा निर्धारण या हिसाब और छूट आदि तकनीकी कार्य हैं और न केवल देश के अन्दर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको करना होता है । भारत में भी कुछ जटिलता कम नहीं है जैसे कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सही रूप से कर प्रशासन को चलाना। भारतीय राजस्व सेवा(उत्पाद एवं सीमा शुल्क) के अधिकारी ही इसको बेहतर रूप से कर सकते हैं क्योंकि उनका एक लम्बा अनुभव है। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी तकनिकी ज्ञान से ओत-प्रोत होते हैं और इनकी अनुभव की वजह से मंदी के समय में भी 27.5 का परोक्ष कर में बढोत्तरी पिछले वर्ष की तुलना में अगस्त 2016 में हुआ । इसलिए नान तकनीकी और सामान्य जानकारी रखने वाले अधिकारियों के कंधे पर कर संग्रहण जैसी अतिमहत्व जिम्मेदारी नहीं सौंपी जानी चाहिए । काला धन को रोकने, कर वंचना, जांच, क्वासी जुडिसियल, कर नीति आदि की जिम्मेदारी भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी ही अच्छी तरह से निभा सकते हैं क्योंकि इनकी महारियत शुरू से ही इस क्षेत्र की है। ग्लोबल फोरम ऑन टैक्स ट्रांस्पैरेसी का नेतृत्व भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी के पास है। यह दुर्भाग्य की बात है जहाँ राजस्व के अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाना है वहीं पर उन्हें हतोत्साहित किया जा रहा है।

वेतन आयोग के चेयरमैन ने अपना अनुभव रिपोर्ट में इस तरह से दिया ''समय अंतराल के साथ आई. ए. एस. ने सारी ताकत अपने अधीन रख ली और दूसरी सेवा के लोगों को पीछे धकेला । सभी जगह चाहे प्रशासनिक हो या तकनीकी पर खुद आई.ए.एस. बैठ गए हैं और यही दूसरी सेवा के अधिकारियों की समस्या का कारण है। अब समय आ गया है कि विशेषज्ञ को महत्त्व दिया जाये जो न केवल सामान्य ज्ञान वाले ही हों। यदि सबको समान व बराबर अवसर नहीं दिया तो आई.ए.एस. और अन्य सेवा के अधिकारीयों के बीच दूरी बढ़ेगी और उससे एक अराजकता की स्थिति का जन्म होगा जो देश के शासन व्यवस्था के लिए उचित नही होगा'' ।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एवं उत्पाद व शुल्क कर बोर्ड के अधिकारियों का अनुभव 20 वर्ष से ज्यादा का है । इन्होंने देश में आई.टी. नेटवर्क और योजनाओं को लागू किया और इनसे उपयुक्त कोई और सेवा के अधिकारी जीएसटी और जीएसटी नेटवर्क का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं। जीएसटी नेटवर्क चलाने का खर्च जब राज्यों एवं केंद्र की सरकारें कर रही हैं तो निजी कंपनियों और लोगों से यह कार्य क्यों कराया जाये और इसके लिए भारी वेतन एवं भत्ता देना पड़ेगा ।

वस्तु एवं सेवा कर की सफलता की जिम्मेदारी उस सेवा के अधिकारियों को दिया जाना चाहिए जो विशेषज्ञ हैं और काउंसिल का सचिव स्थायी और भारतीय राजस्व सेवा (उत्पाद एवं शुल्क) का हो। आज़ाद भारत से अभी तक नौकरशाही को चलाने का कार्य सामान्य अनुभव रखने वाले अधिकारी अर्थात आई. ए. एस. ने किया जिससे तकनिकी एवं विशेषज्ञों की क्षमता का उपयोग न हो सका और दूसरी तरफ वैज्ञानिक, शोधकर्ता, शिक्षक इत्यादि इससे हतोत्साहित हुए हैं। इसके बावजूद भी हम बहुत ज्यादा सबक नहीं ले सके और आज भी सरकारों के सभी अहम पदों पर सामान्य जानकारी और अनुभव रखने वाले अधिकारी कार्यरत हैं। वस्तु एवं सेवा कर सरकार के आय का मुख्य संगठन बनने जा रहा है और इसलिए यह बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण है कि इसको सफल बनाते हुए ज्यादा कर इकट्ठा किया जाये और उससे विकास की परियोजनाए एवं आम जनता की बुनियादी सुविधाओं को अधिकतम पूरा किया जा सके। हम जीएसटी को सफल लागू करने में कोई जोखिम नहीं उठा सकते हैं नहीं तो राष्ट्र के विकास के ऊपर प्रतिकूल असर पड़ेगा ।

डॉ. उदित राज

28 नवंबर की रैली के संबंध में सूचनाएं प्राप्त करने हेतु परिसंघ का ऐप डाउनलोड करें

गत् 30-31 जुलाई को मावलंकर हॉल दिल्ली में आयोजित अनसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के सम्मेलन में तय किया गया था कि आंदोलन की गतिविधियां पूरे देश में प्रचारित करने हेतु सोसल मीडिया का प्रयोग सभी अनिवार्य रूप से करेगें और परिसंघ का ऐप भी डाउनलोड करके इसे इस्तेमाल करेगें लेकिन सोसल मीडिया का उपयोग बहुत ही कम लोगों ने शुरू किया है। परिसंघ का ऐप भी बार-बार एस.एम.एस. द्वारा सूचित करने के बाद भी अभी तक लगभग 500 लोगों ने ही डाउनलोड किया है। सभी साथियों से अपील है कि रैली से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान और गतिविधियों को तेज करने में सोसल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करें और परिसंघ का ऐप https://goo.gl/qNfYK9 लिंक से डाउनलोड करें या डाउनलोड लिंक प्राप्त करने के लिए 011-66978003 पर मिसकाल करें। किसी प्रकार की समस्या हो तो कार्यालय में सुमित - 9868978306 से सम्पर्क करें।

- डॉ. उदित राज, राष्ट्रीय अध्यक्ष

28 नवंबर की रैली की तैयारी हेतु डॉ0 उदित राज के आगामी कार्यक्रम

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ राष्ट्रीय चेयरमैन, डॉ0 उदित राज द्वारा रैली की तैयारी हेतु विभिन्न प्रदेशों का दौरा किया जा रहा है। उनके प्रमुख कार्यक्रम नीचे छापे जा रहे हैं। परिसंघ के प्रदेश, जिला एवं अन्य इकाइयों के पदाधिकारियों को भी विभिन्न स्थानों पर रैली की तैयारी हेतु कार्यक्रम किया जाना चाहिए। वॉयस ऑफ बुद्धा के सभी अंकों में हैंडबिल और पोस्टर का नमूना छापा जा रहा है, इसमें स्थानीय नेताओं के नाम शामिल करके अधिक से अधिक संख्या में छपवाकर वितरित करें।

2 अक्टूबर, 2016
परिसंघ की जनसभा
सीनः अम्बेडकर भवन,
बागा हास्पिटल
यमुनानगर, हरियाणा
समय : दोपहर 12 बजे
सम्पर्क : श्री ताराचंद कंडोलिया,
मो. 9355330849

5 अक्टूबर, 2016
नेशनल एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. एवं यूथ फ्रंट का महाराष्ट्र राज्य अधिवेशन
स्थान : केशवराव भोसले नाट्यग्रह,
कोल्हापुर, महाराष्ट्र
समय : 11 बजे
सम्पर्क : हर्षवर्धन दवने,
मो. 7709975562

8 अक्टूबर, 2016
परिसंघ की जनसभा
स्थान : रॉयल पैलेस, अपोजिट देवी विहार
(मोहन स्पिनिंग मिल), सर्कुलर रोड, रोहतक, हरियाणा
समय : 10 बजे
सम्पर्क : राजेन्द्र प्रसाद,
मो. 9813731984

10 एवं 11 अक्टूबर, 2016
परिसंघ की जनसभा
स्थान : रविभवन कांफ्रेंस हॉल,
नागपुर, महाराष्ट्र
सम्पर्क : दीपक तभाने,
मो. 09764830810

18 अक्टूबर, 2016
परिसंघ की जनसभा
स्थान : जेल गोरा गेस्ट हाउस,
कम्युनिटी हॉल, नियर झरिया,
धनबाद, झारखंड
समय : प्रातः 11 बजे
सम्पर्क : बी.एन. प्रसाद,
मो. 9199368704

20 अक्टूबर, 2016
परिसंघ का सम्मेलन
रेल व्हील फैक्ट्री, यलहंका,
बंगलौर, कर्नाटक
समय : प्रातः 10 बजे से अपराह्न 2 बजे
सम्पर्क : चन्नप्पा,
मो. 8553621291

23 अक्टूबर, 2016
परिसंघ का महाराष्ट्र राज्य का महाअधिवेशन
स्थान : गर्बे हॉल, बुल्डाना, महाराष्ट्र
समय : दोपहर 12 बजे
सम्पर्क : उद्धव मूले,
मो. 09922899969

24 अक्टूबर, 2016
परिसंघ की जनसभा
स्थान : पिंगला ऑडिटोरियम हॉल, पोस्ट एंड थाना - पिंगला, पश्चिम मिदिनापुर, पश्चिम बंगाल
समय : 11 बजे
सम्पर्क : श्री सुबराता बातूल,
मो. 9932109066

25 अक्टूबर, 2016
कस्टम एवं सेंट्रल इक्साइज के अधिकारियों कर्मचारियों की सभा
स्थान : सेंट्रल एक्साइज ऑडोटेरियम, हॉल शांतिपैली, नियर रुबी हास्पिटल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
समय : अपराह्न 1 बजे
सम्पर्क : पी. बाला,
मो. 9831083430

6 नवंबर, 2016
परिसंघ का सम्मेलन
ऑडोटेरियम, सी.एस.जे.एम. यूनिवर्सिटी,
जी.टी. रोड, कानपुर
समय : प्रातः 10 बजे
सम्पर्क : सुशील कमल,
मो. 9807416045

आगामी रैली से संबंधित हैंडबिल का नमूना छापा जा रहा है। परिसंघ के नेताओं से अपील है कि प्रदेश एवं जिला इकाइयों की ओर से भी छपवाकर वितरित करें।

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ

के तत्वावधान में

19वीं महा रैली

28 नवंबर, 2016
रामलीला मैदान, नई दिल्ली

डॉ. उदित राज
पूर्व आईआरएस
राष्ट्रीय अध्यक्ष

साथियो,

हम दलितों, आदिवासियों एवं पिछड़ों की समस्या केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी है। सरकार किसी की हो समस्याएं कम और ज्यादा के रूप में रहेगीं ही। जहां दलित मुख्यमंत्री रहे हैं, वहां भी अत्याचार होते थे। 1997 में जब सामाजिक न्याय की सरकार केन्द्र में थी तो पांच आरक्षण विरोधी आदेश जारी हुए थे। बाबा साहब ने कहा था कि राजनैतिक जनतंत्र तभी सफल होगा जब सामाजिक जनतंत्र कायम होगा और इसके लिए सामाजिक परिवर्तन - जैसे बौद्ध धम्म की दीक्षा, पाखंड का त्याग, जातिविहीन समाज, कम से कम दलितों में जात-पांत का खात्मा आदि। इससे यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि हर हाल में हजारों वर्षों की असमानता और शोषण से हम सभी को स्वयं तो लगातार लड़ना ही होगा, सरकार चाहे जिसकी हो। मां-बाप ने जन्म दिया लेकिन आरक्षण बाबा साहब के प्रयास से मिला। आरक्षण केवल अपने उपभोग के लिए ही नहीं है, बल्कि संघर्ष करने के लिए। इसलिए चाहे मंत्री हों या सांसद या प्रधान या अधिकारी-कर्मचारी सभी समाज के सशक्तिकरण के लिए प्रतिनिधि हैं। झज्जर (हरियाणा) में गाय की खाल की खातिर 5 दलितों को मौत के घाट उतार दिया गया और हाल में उना (गुजरात) में क्या हुआ, हम सभी जानते हैं। अभी भी हमें कुछ लोग जानवरों से बदतर समझते हैं।

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ का गठन 1997 में 5 आरक्षण विरोधी आदशों की वापिसी के लिए हुआ और उसके बाद धरना-प्रदर्शन व आंदोलन शुरु हुआ। 11 दिसंबर, 2000 को रामलीला मैदान, दिल्ली की रैली आज़ाद भारत की सबसे बड़ी रैलियों में से एक थी और सरकार पर दबाव बना जिसकी वजह से 81वां, 82वां एवं 85वां संवैधानिक संशोधन हुए और छिने अधिकार वापिस मिले। 4 नवंबर, 2001 को लाखों लोगों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दिलाई। निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए संघर्ष की शुरुआत हमने ही की। 2006 में सुप्रीम कोर्ट में नागराज के नाम से मशहूर मुकदमा जो 85वें संवैधानिक संशोधन से संबंधित था, की पैरवी हमने ही की और जीते। पिछड़ों को उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के खिलाफ सवर्णों के आंदोलन का भरपूर विरोध किया और इस अधिकार को लेकर रहे। अन्ना हजारे के आंदोलन के कारण जो लोकपाल बिल बन रहा था हमने बहुजन लोकपाल बिल पेश करके उसमें आरक्षण कराया। वरना दलितों व पिछड़ों को जातीय आधार पर फर्जी मामले में फंसाने का यह सबसे बड़ा प्लेटफार्म बनता। 2008 में तत्कालीन उ0प्र0 की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती द्वारा आदेश जारी किया गया कि अनुसूचित जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत 22 अपराधों में से सिर्फ बलात्कार एवं हत्या के मामले ही दर्ज किए जाएंगें, शेष मामलों में यह एक्ट नहीं लगेगा। तब हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करके इसे दुरुस्त कराया। इस अधिनियम में दिसंबर 2015 में संसद में संशोधन हुआ और अब 123 प्रकार के अपराध इसमें शामिल हैं।

पदोन्नति में आरक्षण का विधेयक संसद से पास होना है। आशा थी कि अब तक हो जाना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसे कराने के लिए महासंघर्ष करना पड़ेगा। जब से डॉ. उदित राज सांसद बने हैं, कोई अवसर नहीं छोड़ा, सवाल उठाने का और शायद ही कोई और सांसद इतना किया होगा (इसे बेबसाइट www.uditraj.com/gallery/video vkSj www.youtube.com/user/druditraj पर देखा जा सकता है)। निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए संसद में डॉ0 उदित राज ने प्राइवेट मेंबर बिल प्रतिस्थापित किया है। निजी क्षेत्र में आरक्षण क्या सवर्णों को चाहिए? डॉ. उदित राज ने अपना काम कर दिया है, समाज क्यों सो रहा है? क्यों नहीं लाखों-करोड़ों सड़क पर उतरते और सभी दलों पर दबाव डलवाकर संवैधानिक संशोधन कराकर निजी क्षेत्र में आरक्षण का अधिकार लें। आउट सोर्सिंग, ठेकेदारी और एडहाक नियुक्ति के जरिए आरक्षण लगभग आधा खत्म किया जा चुका है। इसके खिलाफ तो संघर्ष करना ही है लेकिन बिना निजी क्षेत्र में आरक्षण लिए गुजारा नहीं होगा। खाली पदों पर भर्ती, ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति, एक राज्य के जाति प्रमाण-पत्र की सभी राज्यों में मान्यता, समान शिक्षा, सफाई कर्मचारियों का नियमितीकरण आदि मांगों को लेकर 28 नवंबर, 2016 (सोमवार) को प्रातः 11 बजे भारी संख्या में विशाल रैली में शामिल होकर ऐसा कर दिखाएं कि यह अधिकार मिलकर रहे।

निवेदक

ब्रह्म प्रकाश, परमेन्द्र, विनोद कुमार, रवीन्द्र सिंह, एन.डी. राम, रामनंदन राम (दिल्ली), जगजीवन प्रसाद, धर्म सिंह, केदारनाथ, सुशील कुमार, नीरज चक, निर्देश कुमारी (उ.प्र.), सिद्धार्थ भोजने, दीपक तभाने, संजय कांबले, सिद्धार्थ कांबले, सूर्यकांत किवांडे (महाराष्ट्र), एस.पी. जरावता, डॉ. मुख्तियार सिंह, महासिंह भूरानिया (हरियाणा), तरसेम सिंह, दर्शन सिंह चंदेढ़, रोहित सोनकर (पंजाब), विश्राम मीना, रंजीत मीना, एम.एल. रासु, मुकेश मीना (राजस्थान), हरिश्चंद आर्या (उत्तराखंड), आलेख मलिक, डी.के. बेहरा (उड़ीसा), परमहंस प्रसाद, नरेन्द्र कुमार (म.प्र.), रामूभाई वाघेला, एन.जे. परमार, नवल सोलंकी (गुजरात), एस. करुपइया, पी.एन. पेरुमल (तमिलनाडु), के. कृष्णन कुट्टी, बाला कृष्णन (केरल), मधु चन्द्रा (मणिपुर), के. महेश्वर राज, प्रकाश राठौर, जे. बी. राजू (तेलंगाना), डॉ. श्याम प्रसाद (आंध्र प्रदेश), अनिल मेश्राम, हर्ष मेश्राम (छ.ग.), कमल कृष्ण मंडल, रामेश्वर राम, सपन हलदर, विश्वजीत साह (प. बंगाल), मधुसूदन कुमार, दिनेश कुमार, एल.एम. ओरांव (झारखंड), आर.के. कलसोत्रा (जम्मू व कश्मीर), मदन राम, कुमार धीरेन्द्र, शिवधर पासवान (बिहार), जे. श्रीनिवासलू, चन्नप्पा (कर्नाटक), सीताराम बंसल (हि.प्र.), प्रदीप बास्फोर (असम).

www.facebook.com/parisangh.all.india
9717046047
@Parisangh1997
parisangh1997@gmail.com

Corres.: T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-1
Tel: 011-23354841-42, 09013869549 Telefax: 011-23354843

डॉ. उदित राज ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अजा/जजा वर्ग से न्यायाधीश नियुक्त करने की मांग की

डॉ. उदित राज, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ ने प्रधानमंत्री महोदय को 24 मई, 2016 को पत्र लिखा था कि अनुसूचित जाति/जन जाति, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं को संवधिान की धारा 124 एवं 217 में संशोधन करके उच्च न्यायपालिका एवं उच्चतम न्यायालय नियुक्ति की जाए। 31 मार्च, 2002 की राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट जो संविधान का निरीक्षण करने के संदर्भ में थी, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस श्री एम.एन. वेंकटचेलैया के नेतृत्व में बनी थी, एस.पी. गुप्ता केस एवं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड केस में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के सर्कुलर में इस बात का समर्थन किया था कि राज्य सरकारें एवं उच्च न्यायालय जजों की नियुक्ति के समय अजा, जजा, पिछड़े, अल्पसंख्यक एवं महिला जजों को उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के जज हेतु समर्थन करें। डॉ. उदित राज जी ने इस रिपोर्ट का हवाला भी अपनी पत्र में दिया। इस विचार का समर्थन सांसद श्री करिया मुंडा के नेतृत्व वाली अनुसूचित जाति/जन जाति से संबंधित पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी 15 मार्च, 2000 की रिपोर्ट और सांसद, डॉ. ई.एम. नाचियप्पन के नेतृत्व वाली पार्लियामेंट्री कमेटी ने जजेज (इन्क्वाइरी) बिल, 2006 जिसने अपनी रिपोर्ट राज्य सभा को 17 अगस्त, 2007 को सौंपी, ने भी किया। इसलिए डॉ. उदित राज ने मांग की कि सरकार अति शीघ्र संविधान की धारा 124 एवं 217 में संशोधन करके अनुसूचित जाति/जन जाति, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं को उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय में भागीदारी सुनिश्चित कराए।

श्री पी. पी. चौधरी, कानून एवं न्याय राज्य मंत्री, भारत सरकार, का जवाब

कानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, से 9 अगस्त, 2016 को इसका जवाब आया कि संविधान की धारा 124 एवं 217 में संशोधन का सरकार द्वारा अभी कोई विचार नहीं किया जा रहा है। वर्तमान समय में अनुसूचित जाति, जन जाति, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं को जजों की नियुक्ति में आरक्षण का अभी कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि सरकार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से अनुरोध कर रही है कि वे न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव भेजते समय योग्य अनुसूचित जाति, जन जाति, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के नाम भेजें।

ऐसे में हमें क्या करना चाहिए

अनुसूचित जाति, जन जाति, अल्पसंख्यक एवं महिलाओं का प्रतिनिधित्व उच्च न्यायालयों में शून्य है। मृत्यु दंड पाए हुए दोषियों में सबसे अधिक संख्या अनुसूचित जाति, जन जाति एवं मुसलमानों की है। भारत ही दुनिया में एक ऐसा देश है, जहां पर जजों की नियुक्ति जजों के द्वारा ही की जाती है। जब नेशनल ज्यूडिशियल एप्वांइटमेंट कमीशन बिल संसद में पास हुआ तो एक आशा की किरण नजर आयी कि अनुसूचित जाति/जन जाति, अल्पसंख्याकों एवं महिलाओं को न्यायपालिका में भागीदारी मिलेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी गैरकानूनी करार कर दिया है। वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय में एक भी जज दलित वर्ग से नहीं है।

कानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, का इस प्रकार का जवाब बहुत ही निराशाजनक है और ऐसा प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में अजा, जजा, पिछड़ों एवं महिलाओं की भागीदारी नहीं हो पाएगी। अभी लगभग 400 जजों की बैकलाग पदों पर नियुक्ति होनी है और एक बार जब इतनी संख्या में बैकलॉग भर जाएगा तो आने वाले 15-20 सालों तक पद खाली नहीं होगें। डॉ0 उदित राज एवं परिसंघ के नेताओं के अलावा किसी को इसकी चिंता नहीं है। आगामी 28 नवंबर को रामलीला मैदान, दिल्ली में होने वाली रैली में न्यायपालिका में आरक्षण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा। आप सभी को पत्र लिखकर, सोसल मीडिया और अन्य माध्यमों से मांग करनी चाहिए कि अभी जो जजों की नियुक्ति की जानी हैं, उनमें अजा/जजा एवं पिछड़ों को आरक्षण मिले।

+++

आगामी रैली से संबंधित पोस्टर का नमूना छापा जा रहा है। परिसंघ के नेताओं से अपील है कि प्रदेश एवं जिला इकाइयों की ओर से भी छपवाकर वितरित करें।

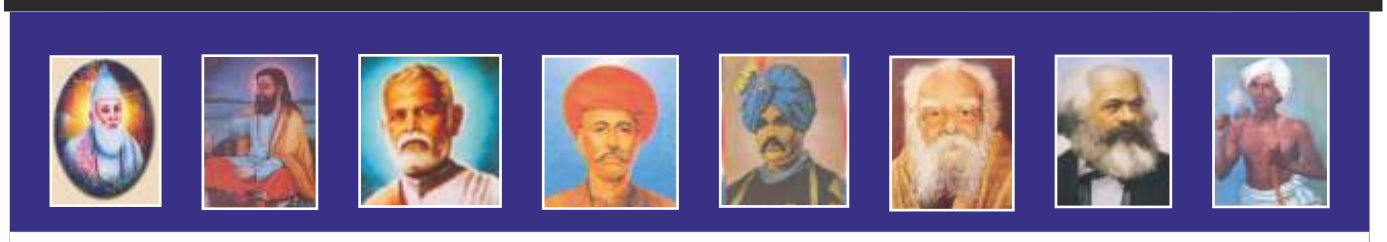

अगर सांवली रात खूबसूरत है तो.....

(पृष्ठ 1का शेष)

यह बताने की जरूरत नहीं समझती, इतना तो आप समझ ही चुके होंगे।

खैर, गोरे रंग को खूबसूरती का पैमाना मानने वाले आज भी सांवले रंग को नीचा बताने में पीछे नहीं रहते। इसका परिणाम, कई सांवली लड़कियां अपना पूरा आत्मविश्वास खो देती हैं, अपने अंदर के तमाम गुणों को भूल कर सांवलेपन के अफ़सोस और शर्म में जीने लगती हैं और लग जाती है खुद को गोरे बनाने की जुगत में। लेकिन शायद वे यह नहीं समझती कि ऐसा करके वे खुद उस तथाकथित समाज के भ्रम में फंसकर सांवलेपन का मज़ाक उड़ाने में लग जाती है।

फिल्म दिलवाले में काजोल की वापसी के साथ उनका एक नया रूप भी देखने को मिला। सांवली सी काजोल अब गोरेपन के आवरण के साथ दिखी। जाहिर ही बात है, उन्होंने सांवले से गोरे होने के लिए तमाम महंगे ट्रीटमेंट का सहारा लिया होगा। खैर, यह उनका व्यक्तिगत चुनाव होगा, मगर उनके इस चुनाव के बाद आज वह हम सांवली लड़कियों के लिए सिर्फ एक कलाकर और एक अभिनेत्री भर ही रह सकीं, जबकि नंदिता दास आज तमाम सांवली लड़कियों की प्यार हैं। काजोल गोरेपन की चाहत के साथ तो आपने खुद ही सांवलेपन का मज़ाक उड़ाया है।

इति शरण

बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि समाज से सांवलेपन के दोयम दर्जे के व्यवहार को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हमें खुद अपने सांवले रंग से प्यार करना सीखना होगा।

अगर सांवली रात खूबसूरत है तो सांवला चेहरा कैसे बुरा हो सकता हैं? सांवली लड़कियों कभी अपने सांवले रंग को लेकर उदास मत होना। बहुत खूबसूरत है यह सांवला रंग। कहने दो दुनिया को जो कहना है। तुम्हारे सांवले रंग के कारण तुमसे कोई शादी करने से मना करता है तो खुश हो, क्योंकि ऐसे इंसान की हमें जरुरत भी नहीं। अगर तुम्हारे सावले रंग के लिए तुम्हारे प्रति कोई बेचारगी प्रकट करता है तो करने दो, क्योंकि तुम्हारा रंग नहीं बल्कि उसकी सोच बदसूरत है। उन तमाम फेयरनेस क्रीम को कह दो नहीं जरुरत हैं हमें तुम्हारी।

और अंत में बहुत-बहुत शुक्रिया नंदिता दास तुम्हारे इस शब्द के लिए stay unfair, stay beautiful and Dark is beautiful.

http://www.streekaal.com/2016/01/blog-post_28.html?m=1

Sample of the Handbill for the forthcoming Rally is being published. It is an earnest appeal to the Confederation Leaders that they should get it printed on behalf of State and District Units and distribute.

All India Confederation of SC/ST Organisations

19th Maha Rally

On

28 Nov 2016

at

Ramlila Ground, New Delhi

Dr. Udit Raj
National Chairman

Friends,

The problems faced by us, Dalits, tribals and backwards, are not just political, but due to social and economic reasons also. Whosoever may be in power, atrocities and discrimination will continue. Atrocities against us have occurred even where a Dalit was the Chief Minister. Dr. Ambedkar had said that without social democracy, political democracy will be meaningless, and for this, we must change society - through deeksha into Buddhism, abolition of superstitions, creation of a caste less society; at least, caste divisions amongst Dalits must be annihilated. Through all this, we can understand that thousands of years of inequalities and exploitation must be fought regularly, even if the Government is headed by Dalits or backwards. 5 anti-reservation orders were issued by DOPT when there was Social Justice Government at Centre. When Ku. Mayawati was the Chief Minister; we lost reservation in promotion case in Lucknow High Court. These examples make it amply clear the need to struggle on a regular basis. Our parents gave birth to us, but we got reservation only through the efforts of Dr. Ambedkar. Reservation was given not only for our own benefits, but to fight for other deprived brothers and sisters. This is why, irrespective of whether one be a Minister or a Member of Parliament or a sarpanch or an officer; they are all responsible to fight for the empowerment of society. In Jhajjar, Haryana 5 Dalits were killed for skinning the carcass of a dead cow; everyone knows the recent happenings in Una in Gujarat. Still, some people treat us as less than animals.

The All India Confederation of SC/ST Organisations was formed in 1997 to fight against 5 anti-reservation orders, and our fight began through rallies, agitations etc. The rally organised by the Confederation on 11th December 2000 at Ramlila Maidan, New Delhi was one of the largest in the history of independent India; this built pressure on the Govt., the 81st, 82nd and 85th Constitutional Amendments were passed and reservation was saved. On 4th November 2001, lacs of people took deeksha into Buddhism under the leadership of the Confederation. In 2006, we fought and won the Nagaraj case in the Supreme Court, related to the 85th Constitutional Amendment. We stood with OBC reservation in higher education in 2006. When the Anna Hazare movement pressed for a Lokpal Bill, we agitated against it and presented the Bahujan Lokpal Bill, and due to that, reservation was introduced here as well. Otherwise, the Lokpal could have become the largest platform for exploitation of SC/STs and OBCs by bringing fictitious cases of corruption.

In 2008, Ku. Mayawati, the then Chief Minister of Uttar Pradesh, passed orders that the Prevention of Atrocities Act, 1989, which included 22 atrocities, be applied only in cases of murder and rape. Then we fought against this in the Allahabad High Court by filing a Public Interest Litigation and it was restored to its original form. This Act was amended by Parliament in 2015, which included 123 atrocities. The Bill for reservation in promotion was to be passed by Parliament - it had been hoped that the Bill would be passed by now, but that has not happened. We have to start off a revolution to get this Act passed. From the time Dr. Udit Raj became a Member of Parliament, he has not left any opportunity to raise issues related to SC/STs in Parliament; it is likely that no other M.P. has raised as many issues – www.uditraj.com/gallery/video & www.youtube.com/user/druditraj

Dr. Udit Raj has introduced a private member Bill for reservation in the private sector in Parliament. Do the forward castes need reservation in private sector? Dr. Udit Raj has done his duty - why is society still sleeping? Why have lacs and crores of people not come out on the street and pressured political parties to pass a Constitutional Amendment for reservation in the private sector? More than half of reservation has already been diluted by outsourcing, contract system and ad hoc appointments. We have to continue fighting against this, but we cannot survive without reservation in private sector. To fight for our main demands of filling up of backlog vacancies, stopping outsourcing and contract system, regularization of safai karamcharis, caste certificates issued by one state being valid throughout the country, equal education etc., you must participate in the rally on 28th November 2016 at Ramlila Maidan, New Delhi at 11 AM to ensure that we get our rights.

By :

Brahm Prakash, Parmendra, Vinod Kumar, Ravindra Singh, N. D. Ram, Ramnandan Ram, (Delhi), Jagjivan Prasad, Dharam Singh, Kidarnath, Sushil Kumar, Neeraj Chak, Nirdesh Kumari (UP), Siddhartha Bhojane, Deepak Tabhane, Sanjay Kamble, Siddhartha Kamble, Suryakant Kiwande (Maharashtra), S. P. Jarawata, Dr. Mukhtiyar Singh, Mahasingh Bhurania (Haryana), Tarsem Singh, Dharshan Singh Chanded, Rohit Sonkar (Punjab), Vishram Meena, Ranjeet Meena, M.L. Rasu, Mukesh Meena (Rajasthan), Harishchand Arya, (U.K.), Alekh Malik, D. K. Behera (Orissa), Param Hans Prasad, Narender Kumar (M.P.), Ramubhai Vaghela, N.J. Parmar, Naval Solanki (Gujarat), S. Karuppaiah, P. N. Perumal (Tamilnadu), K. Krishnan Kutty, Bala Krishnan (Kerala), Madhu Chandra (Manipur), K. Maheshwar Raj, Prakash Rathor, J. B. Raju (Telangana), Dr. Shyam Prasad (A.P.), Anil Meshram, Harsh Meshram (Chhattisgarh), Kamal Krishna Mandal, Rameshwar Ram, Sapan Haldar, Vishwajit Shah (W. Bengal), Madhusudan Kumar, Dinesh Kumar, L. M. Oraon (Jharkhand), R. K. Kalsotra (J & K), Madan Ram, Kumar Dhirendra, Shivdhar Paswan (Bihar), J. Shriniwaslu, Channappa (Karnataka), Sitaram Bansal (H.P.), Pradeep Basfor (Assam)

www.facebook.com/parisangh.all.india
9717046047
@Parisangh1997
parisangh1997@gmail.com

Corres.: T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-1
Tel: 011-23354841-42, 09013869549 Telefax: 011-23354843

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशि:

पांच वर्ष : 600 रुपए

एक वर्ष : 150 रुपए

Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of **'Justice Publications'** at T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution:
Five years : Rs. 600/-
One year : Rs. 150/-

American Psychological Association To Classify Belief in God As a Mental Illness

According to the American Psychological Association (APA), a strong and passionate belief in a deity or higher power, to the point where it impairs one's ability to make conscientious decisions about common sense matters, will now be classified as a mental illness.

The controversial ruling comes after a 5-year study by the APA showed devoutly religious people often suffered from anxiety, emotional distress, hallucinations, and paranoia. The study stated that those who perceived God as punitive was directly related to their poorer health, while those who viewed God as benevolent did not suffer as many mental problems. The religious views of both groups often resulted in them being disconnected from reality.

Dr. Lillian Andrews, professor of psychology, stated, "Every year thousands of people die after refusing life-saving treatment on religious grounds. Even when being told 'you will die without this treatment' patients reject the idea and believe that their God will still save them. Those lives could be saved simply by classifying those people as mentally unfit for decision making."

"Jehovah Witnesses for instance," Dr. Andrews continued, "will not accept blood under any circumstance. They would rather die than to receive life-saving donor blood. Many religious people believe they have "healing power" in their hands. Many believe they can communicate with God using a personal language, which is unknown to anyone but the communicator and God (known as speaking in tongues). Many often tell of seeing spirits. All of these are signs of a mental break and a loss of touch with reality. Religious belief and the angry God phenomenon has caused chaos, destruction, death, and wars for centuries. The time for evolving into a modern society and classifying these archaic beliefs as a mental disorder has been long overdue. This is the first of many steps to a positive direction."

With the new classification, the APA will lobby to introduce legislation which would allow doctors the right to force life-saving treatment on those who refuse it for spiritual reasons on the grounds that they are mentally incapable of making decisions about their health.

The American Psychological Association says more information about the study and the new classification will be made available to the public in their upcoming journal (which is expected to be release in early August).

- By Kato Leonard

http://www.thenewsnerd.com/health/apa-to-classify-belief-in-god-as-a-mental-illness/

Australians Are Converting Into Buddhists For A Surprising Reason

By Afsha Khan

There is an peculiar change noticed in the spiritual landscape of Australia these days. This country is becoming multicultural by readily accepting the cultures that were earlier considered foreign to Anglo-European Australians. Buddhism is a resilient religion that is rapidly gaining popularity in Australia. Buddhism follows a 2,500-year-old philosophy which is 500 years older to Christianity and 1000 years to Islam.

All the other ancient religions such as the sun worshippers of Ancient Egypt, the human sacrifices of the South American Mayans and the Druids from the Dark Ages of England have faded with time but Buddhism is rapidly growing in many western countries.

Let's check out the story and the pictures depicting the unconventional rise of Buddhism in Australia.

Australians are voluntarily getting converted to Buddhism. The surprising fact is that the maximum converts to Buddhism are well-educated middle-aged professionals of Australia. People are actively converting to Buddhism in seek of inner peace.

Buddhism has a major role in the history of Australia. It was actually the earliest non-indigenous religion that existed even before Christianity in the country.

Buddhists reach Australia even before the Whites.

The Chinese Ming emperor, Cheng-Ho sent 62 large ships to explore Southern Asia between 1405 and 1433. But, several ships reached to the north of Arnhem Land instead of Indonesia.

However, the first documented arrival of Buddhists in Australia was witnessed in 1848.

During the gold rushes, Chinese coolie laborers arrived in Australia for digging the Victorian gold fields but they returned to their homeland within 5 years.

The first permanent Buddhist community was established in 1876 in Australia.

Sinhalese migrants were the ethnic Sri Lankans who built the temple on Thursday Island while they were deployed to work on the sugarcane plantations in Queensland.

Many Japanese Shinto Buddhists also migrated to Australia in search of work.

From the late 1870s onwards, some Buddhists used to work in the pearling industry across northern Australia. Buddhists formed their separate community and maintained their own cemeteries.

Buddhists introduced their festivals, benefits of mind training and meditation to Australians.

The earliest known Buddhist organization 'The Little Circle Of The Dharma' was formed by a small group of committed Buddhists in Melbourne, Australia in 1925. The Buddhist Society of New South Wales is another famous Buddhist group in Australia which has the maximum membership of Anglo-European people.

By 1958, Buddhism spread in Western Australia, South Australia, Queensland and Victoria.

Sri Lankan monk, Somaloka established the first monastery in Australia in 1971. A number of monasteries soon spread across the nation. Besides Australia, Hollywood is also fascinated with this religion. Hollywood filmmakers made films depicting Buddhism such as Seven Years in Tibet, Kundun etc.

Successive visits of Dalai Lama to Australia helped in making Buddhism an important minority religion in the country. The number of Buddhists is steadily increasing in the nation which is pointing towards the dissatisfaction of Australians to their religious beliefs.

It can be said that Buddhism is more competitive than Christianity in Australia.

Australians are fascinated with Buddhism because this religion not only take refuge from the world of chaos but also allows to reinvent the own personal spirituality in this materialistic world. Technically, Buddhism is not a religion; it is just a psychology and a philosophy with a moral code of mind training.

https://www.wittyfeed.com/story/19728/australians-turning-into-buddhists

State conference of Tamil Nadu Confederation

Dr. Udit Raj with S. Karuppaiah and others

The Tamil Nadu State Unit of the All India Confederation of SC/ST Organisations organised a state level conference of the Confederation in Chennai on 17th September 2016. Dr. Udit Raj, National Chairman participated in the Conference as the Chief Guest, and Shri S Karuppiah, Tamil Nadu State President of the Confederation chaired the Conference. Members and office bearers of the constituent units of the Confederation from Central Public Sector Undertakings, Government departments and NGOs from all over Tamil Nadu participated in the Conference. Dr. Ambedkar Awards were given at the Conference to eminent persons in recognition of their distinguished service and unmatched support to the Confederation for development of SC/STs.

Dr. Udit Raj spoke about the achievements of the Confederation and its present aims, and current threats to reservation. He also spoke about the need to immediately pass a Bill for reservation in private sector, need to stop caste based violence and discrimination of employees. He also spoke about the need to utilise social media to the hilt for success of the movement. Dr. Raj also elaborated about his reasons for joining BJP, and about the several issues he has raised for the welfare and benefit of SC/STs in Parliament.

The following resolutions were passed during the Conference

1. As per Article 16 (4) (A) of the Constitution, reservation in promotion was extended to SC/ST employees. However, the Supreme Court has ordered the Government to clear up the level to which reservation in promotion should be given, which has nullified the benefits of reservation in promotion, particularly, in PSUs, Public Sector banks etc. The Conference urged the Government to immediately pass the reservation in promotion Bill which is pending in the Lok Sabha and also to pass the necessary orders for providing reservation in promotion for SC/STs in all posts

2. The new economic policy of the Government has encouraged privatisation to a great extent and hence, SC/STs are being affected as there is no provision of reservation in the private sector due to which employment opportunities for SC/STs in the private sector are very low. The private sector enjoys several concessions and privileges given by the Government, and therefore has a much greater responsibility to society. Hence, the Conference urged the Government to immediately bring into force suitable legislation providing reservation for SC/STs and OBCs in the private sector. The Bill for reservation in promotion has already been introduced by Dr. Udit Raj in the Lok Sabha, and it should be implemented in letter and spirit for the benefit of the downtrodden community

3. The lower judiciary, there is reservation for SC/STs, however there is no system of reservation in appointments in the higher judiciary. Successive governments at the centre have been insisting on an inclusive policy, however the present collegium system has not been able to ensure adequate representation of SC/STs in the higher judiciary - there is not even a single SC/ST judge in the Supreme Court, and very meagre representation in all 24 High Courts. Therefore, the conference urges the Government to ensure immediate appointment of adequate number of SC/STs in the higher judiciary

4. Reservation policy is not strictly implemented in appointments to teaching

urges the Ministry of Human Resource Development, Government of India to issue orders for strict adherence to the policy of reservations in appointments to teaching positions in all institutes of higher learning

5. The Special Component Plan for SCs has been implemented since 1980; in the absence of effective review and monitoring mechanisms, funds allocated under SCP/TSP have not yielded desired results. The conference urges the Government of India to enact a special legislation for effective implementation of SCP and TSP funds

6. The conference appreciated the decision by the Government of Tamil Nadu in providing 50% reservation for women in local body posts, and urged the Government to make necessary rules for providing 19% reservation for women belonging to the SC/ST community in the 50% quota. The conference also

Presidents

7. The Government of Tamil Nadu had assured the Hon'ble High Court of Madras that it would clear huge SC/ST backlog vacancies in Tamil Nadu state government services, which have remained unfilled for decades. The conference urged the Government of Tamil Nadu to clear all backlog vacancies through a special recruitment drive

8. Pursuant to the directions of the Hon'ble High Court of Madras, the Government of Tamil Nadu has constituted a committee to retrieve Panchami lands in Tamil Nadu. The conference urges the Government of Tamil Nadu to retrieve Panchami lands and redistribute them to landless Dalits in a time bound manner

9. The conference expressed its deep concern about the increase of incidences of caste violence in the name of honour killings. The conference reaffirmed and reposed its faith in inter caste marriages as a means to annihilate casteism. The conference therefore urged both Central and state governments to take stringent action against perpetrators of such violence by setting up special trial courts at the District level

10. The conference expressed deep concern about the inordinate delay in setting up of Tamil Nadu state SC and ST Commission despite directives from the Hon'ble High Court of Madras, placing the Government in a position of contempt of court. The conference urged the Government of Tamil Nadu to take urgent action for setting up of a state commission for SC/STs

11. Huge number of upper caste people got benefits and employment in Government jobs meant for SC/STs by obtaining bogus caste certificates. The conference urged the Government to immediately verify genuineness of SC/ST community certificates within 30 days

12. SC/STs living in Delhi are not allowed to use community certificates issued by the Government of Tamil Nadu to avail benefits of reservation in Tamil Nadu. The conference urged the Government of Tamil Nadu to include castes such as Adhi-Dravidar, Pallar/Pallan, Paraiyar/Parayanand Arundadiyar in the Gazette notification of Delhi Government for the benefit of 10 - 15 lac SC/ST people from Tamil Nadu living in Delhi. Dr. Udit Raj, MP raised this issue in Parliament, the

(Contd. on page 8)

Dr. Udit Raj while addressing the conference

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 19 ● Issue 21 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● Total Pages 8 ● 16 to 30 September, 2016

Preparation meeting for success of rally on 9 Oct at Mavlankar Hall, Delhi

It is necessary to hold a meeting of main leaders and workers of the Confederation for the success of the rally to be held on 28th November 2016. Keeping this in mind, a meeting has been organized on 9th October 2016 Mavlankar Hall, Constitution Club, New Delhi to prepare for the rally. It is not necessary for every to attend the meeting; however, district and state level office bearers of the Confederation must attend. Workers of the Confederation should also attend the meeting, especially those who could not attend the Convention of the Confederation held on 30th and 31st July 2016. Many new people have joined the Confederation; they will also get a chance to attend the meeting. Hence, they are specially invited.

Please do not disappoint us by attending the meeting empty handed. Those who have been issued membership books should submit the books on 9th October, even if they have not been completed. If necessary, fresh books can also be issued. Everyone has already been requested to join us on Facebook, Twitter, Whatsapp and other social media, and also to share names and mobile numbers of activists through email. Those who have already done this should ask others to do the same, and those who have not done anything, should consider it their responsibility to share names and mobile numbers, and join us on social media.

We should remember that no one else will fight for our rights; the day people understand that employees and officers have the same responsibility as politicians, and then no one will be able to stop us from getting our rights. A feeling has been created amongst employees and officers that only Ministers, MPs, MLAs and politicians should fight for our rights, which should be dispelled. Politicians, MPs and MLAs know what their responsibility is and those who do not know cannot be taught this nor can we get much by force. Dr. Ambedkar was saddened by the failure of Dalit intellectuals. Dalit intellectualism is mostly in the hands of employees. The recent Patel and Jat agitations for reservation were led by the people themselves, not by politicians or leaders. If they sat at home expecting something from the leaders, then perhaps these agitations would not have even taken place.

Dr. Udit Raj, National Chairman, SC/ST Confederation

www.facebook.com/parisangh.all.india
9717046047
@Parisangh1997
parisangh1997@gmail.com

Sample of the Poster for the forthcoming Rally is being published. It is an earnest appeal to the Confederation Leaders that they should get it printed on behalf of State and District Units and distribute.

By : Brahm Prakash, Parmendra, Vinod Kumar, Ravindra Singh, N. D. Ram, Ramnandan Ram, (Delhi), Jagjivan Prasad, Dharam Singh, Kidarnath, Sushil Kumar, Neeraj Chak, Nirdesh Kumari (UP), Siddhartha Bhojane, Deepak Tabhane, Sanjay Kamble, Siddhartha Kamble, Suryakant Kiwande (Maharashtra), S. P. Jarawata, Dr. Mukhtiyar Singh, Mahasingh Bhurania (Haryana), Tarsem Singh, Dharshan Singh Chanded, Rohit Sonkar (Punjab), Vishram Meena, Ranjeet Meena, M.L. Rasu, Mukesh Meena (Rajasthan), Harishchand Arya, (U.K.), Alekh Malik, D. K. Behera (Orissa), Param Hans Prasad, Narender Kumar (M.P.), Ramubhai Vaghela, N.J. Parmar, Naval Solanki (Gujarat), S. Karuppaiah, P. N. Perumal (Tamilnadu), K. Krishnan Kutty, Bala Krishnan (Kerala), Madhu Chandra (Manipur), K. Maheshwar Raj, Prakash Rathor, J. B. Raju (Telangana), Dr. Shyam Prasad (A.P.), Anil Meshram, Harsh Meshram (Chhattisgarh), Kamal Krishna Mandal, Rameshwar Ram, Sapan Haldar, Vishwajit Shah (W. Bengal), Madhusudan Kumar, Dinesh Kumar, L. M. Oraon (Jharkhand), R. K. Kalsotra (J & K), Madan Ram, Kumar Dhirendra, Shivdhar Paswan (Bihar), J. Shriniwaslu, Channappa (Karnataka), Sitaram Bansal (H.P.), Pradeep Basfor (Assam)

Corres.: T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-1 Tel: 011-23354841-42, 09013869549 Telefax: 011-23354843

State conference of Tamil Nadu .....

(Contd. from page 7)

Minister replied that no such recommendation was received from the state government

13. The conference also urged the Government of India and the Government of Tamil Nadu to issue suitable orders to prevent caste based attacks, discrimination and humiliation prevailing in the workplace, both in Government and private sectors

In-charge and Research officer from the National Commission for Scheduled Castes Smt. C Chandra Prabha, MA, senior investigators Shri Iniyan and Shri Lister, and other officers from the NCSC participated in the conference. Many leaders of the All India Confederation of SC/ST Organisations from other states such as Shri Braham Prakash, National General Secretary, Delhi, Shri Maheshwar Raj AP state president, Dr. Sanjay Kamble from Mumbai, Shri Chinappa and Shri Rajasekaran from Karnataka also participated in the conference. Other participants in the conference included district presidents and office bearers of the Confederation, A.Anbulingam,D.Kaliyappan and R.Girishkumar from Chennai, M.Vijayan, V.Rajni.D and Radha Jayalakshmi from Salem. Shri K Kumaravelu from Cuddalore district, P Chandran from Sivagangagai and Dr. Bharathi from Trichy participated in the conference and also brought a huge number of supporters.

A number of affiliated organisations also participated in this conference such as CVRDE SC/ST EWA, OCF SC/ST EWA, FCI SC/ST EWA, Southern Railway SC/ST EWA, BSNL SC/ST EWA, NIRT-EPID SC/ST EWA, MMTC SC/ST EWA, CFA SC/ST EWA Dalit Welfare Trust, Airport AI SC/ST EWA, TNSCB SC/ST EWA, CR Dr. BR Ambedkars SC/ST Load Man WA, Urur Adayar Adidravidar Wel. Assn. Shipping Corporation SC/ST EWA, Meteorological Department SC/ST EWA, Madras Fertilisers Ltd Staff Union, Madras Fertilisers Ltd. BC/MBC and OBC Associations, Tamil Nadu Electricity Board SC/ST EWA, Rev. Mahendran, Shri Edison and Shri Raghul from All India Christian Council, Shri A K Mohan from RPI and Teachers Association members.

KARUPPAIAH SUBBAIAH
9894618322

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com Computer typesetting by C. L. Maurya